



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249414
CG-DL-E-13102023-249414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4325]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2023/आश्विन 21, 1945

No. 4325]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2023/ASVINA 21, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4496(अ).—धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पटना न्यायक्षेत्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) दिनांक 5 फरवरी, 2016 की संख्या एसओ 372(ई) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में और संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के मुकदमे के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
“4	बिहार	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना	जिले-पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालन्दा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, भागलपुर (17 जिले)।

		अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XVI, पटना	बेगुसराय, खगड़िया, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया (21 जिले) जिले। ”
--	--	---------------------------------------	---

[फा. सं. सी-18015/3/2023-एडी.ईडी]]

राजीव लोचन, अवर सचिव

फुट नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्या एसओ 372 (ई), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में दिनांक 27 मार्च, 2017 संख्या एसओ 966(ई), के जरिए संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2023

S.O. 4496(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money Laundering Act 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna, the Central Government hereby makes further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii) *vide* number S.O.372(E) dated the 5th February, 2016. In the table to the said notification, for serial number 4 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sl.No.	State or Union Territory	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
“4	Bihar	District and Sessions Judge, Patna	Districts of Patna, Bhojpur, Buxar, Kaimur, Rohtas, Nalanda, Jamui, Munger, Lakhisarai, Sheikhpura, Jehanabad, Arwal, Aurangabad, Gaya, Nawada, Banka, Bhagalpur (17 districts).
		Additional District and Sessions Judge-XVI, Patna	Districts of Begusarai, Khagaria, Saran, Siwan, Gopalganj, East Champaran, Muzaffarpur, Sheohar, Sitamarhi, Vaishali, West Champaran, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Madhepura, Saharsa, Supaul, Araria, Katihar, Kishanganj, Purnea (21 districts).”

[F. No. C-18015/3/2023-Ad.ED)]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and subsequently amended *vide* number S.O. 966(E), dated 27th March, 2017.